एक चुनिंदा दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है जिसका उद्देश्य रोग की स्थानिक-मारिता कीटनाशकों के इस्तेमाल में रोगाणु-प्रतिरोधन क्षमता और परजीवी में औषध प्रतिरोधन क्षमता के आधार पर रोगाणु-रोधी और परजीवी-रोधी उपायों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है । कर्नाटक राज्य में स्तरीकरण का कार्य पूरा हो गया है और इस समय महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में यह कार्य चल रहा है तथा 1992 के दौरान मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में और उसके बाद इसे अन्य राज्यों में चरणबद्ध ढंग से चलाये जाने का प्रस्ताव है । मलेरिया नियंत्रण के लिये आठवीं योजना अवधि में प्रस्तावित विशिष्ट कार्यनीति अन्य बातों के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों में नियंत्रण प्रयासों में तेजी लाने पर आधारित है जहां पर मलेरिया के कारण सर्वाधिक रुग्णता और मत्यु होती हैं ।

अत: केन्द्रीय सरकार का आठवीं योजना अवधि में आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण की एक गहन परि-योजना चलाने का प्रस्ताव है । इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति के विकास कीटनाशी छिड़काव जैव पर्या-वरणिक विधियों अति संवेदनशील वर्गों जैसे गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिये बेडनेट्स के इस्तेमाल जैसे वैयक्तिक सुरक्षा उपाय तथा मलेरिया रोगियों का रोग की आरंभिक अवस्था में ही पता लगाने और उपचार करने पर बल दिया जायेगा । मध्य प्रदेश के बस्तर जिले को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जायेगा ।

River Valley Project for Afforestation

*32. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of .ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to states

(a) whether it is a fact that Government have been assisting State Governments under the River Valley Project for afforestation for soil conservation in catchment areas;

(b) if so, the details thereof alongwith the details of area brought under this scheme so far and proposed to be brought in Orissa; and

(c) whether any such proposal has been received from the Orissa Government in this regard and the details of action taken/achievements made to cover the catchment areas of some flood-prone areas of rivers in Orissa?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) A centrally sponsored scheme of Soil Conservation in the Catchments of River Valley Projects (RVP) is under operation in 27 catchments covering 17 States including Orissa since the Third Plan period. The physical and financial progress with reference to Orissa is as follows:

	Physical area (area in Lakhs 000 ha.)	Financial Rs. in
(i) Agricultural land (upto 1990-91) .	91.07	
(ii) Non-agricultural area .	107.17	
	198.24	2,317.96

An area of 12000 ha. is to be taken up at a cost of Rs. 350 lakh during 1991-92 in Orissa.

(c) Proposal from Govt, of Orissa was received for catchments of Brah-mani, upper Kolab and Indravati under RVP Scheme in 1985. The proposal was not acceded to, as it did not form part of the approved list of catch-ments under RVP.

Indian Railways Welfare Organisation

*33. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :—

(a) whether the railways have started a new organisation called the "Indian Railways Welfare Organisation" to construct houses for serving and retired railway employees ;

(b) if so, the response received from the beneficiaries thereto ;

(c) the places selected by the railways for construction of such houses ;

(d) the places where land has already been acquired ; and

(e) the cost of various categories of houses/flats to be constructed and the facilities for loans to be provided by the railways/other organisations ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF) : (a) Yes, Sir.

(b) About 47,000 beneficiaries have registered themselves as primary members of Indian Railway Welfare Organisation (IRWO).

(c) IRWO has tentatively selected 70 places which include Zonal Railway Headquarters, Divisional Railway Headquarters, State Capitals and other important towns.

(d) Land has been acquired at NOIDA, Gorakhpur, Gurgaon, Calcutta, Madras, Hyderabad, Panchkula, Meerut, Indira-puram, Jaipur and Bombay.

(e) The estimated cost of houses/flats various from Rs. 85,000 to Rs. 6.5 lakh depending on the type of houses, cost of land and technical specifications.

Serving employees can avail of the facility of House Building Advance as per extant rules. In addition, IRWO is co-ordinating with various agencies for getting loans for all the allottees.

"एड्स" तथा अन्धेपन की बीमारी के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

*34. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में "एड्स" तथा अंधेपन की बीमारी को नियंत्रित करने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां तो सरकार इन दो योजनाओं के लिये महाराष्ट्र सरकार को क्या सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ;

(ग) क्या सरकार "एड्स" के रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये ऐसे रोगियों के लिये मुंबई में एक अस्पताल खोलनें का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिये अप्रैल 1987 से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निगरानी रखने, रक्त सुरक्षा को प्रोत्साहन देने एवं एड्स रोगियों के उपचार के लिये सुविधायें विकसित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को सहायता प्रदान की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहायता प्राप्त की गई और 1 जनवरी 1990 से रोकथाम और नियंत्रण सम्बन्धी कार्यकलाप शुरू करने के लिये 43.54 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

(ख) अब एक विस्तृत राष्ट्रीय एड्स परियोजना तैयार की गई है जिसका परिव्यय 270 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को धन की व्यवस्था के लिये विश्व बैंक को भेजा गया। बातचीत अभी हाल ही में संपन्न हुई है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक का एक उदार ऋण सहयोगी) द्वारा 229.5 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान किये जाने की आशा है। यह परियोजना पहली अप्रैल 1992 से पांच वर्ष की अवधि में लागू की जायेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यकलाप शुरू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को नकद और सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जायेगी:–

—कार्यक्रम प्रबंधन;
—निगरानी;
—रक्त सुरक्षा;
—सुरक्षा शिक्षा और संचार;
—यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण;
—कंडोमों के प्रचलन को प्रोत्साहन;
—रोगी उपचर्या ।